



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यपालन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, २८ सोमबर, १९९४/७ अग्रहायण, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-२, ८ नवम्बर, १९९४

सं० एच० एफ० डब्ल्यू-बी० (एफ) ४-१३/९४.—इस विभाग की सभसंल्लेक अधिसूचना, दिनांक १६-९-९४ जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उप-स्वास्थ्य केन्द्र समेज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्थानित कर दिया गया है, के क्रम संख्या-२ पर दर्शाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेज जिल. शिमला के स्थान पर जिला कुल्लू पढ़ा जाए ।

आवास चला

शिमला-2, 8 नवम्बर, 1994

सं० एन० एफ० डी० बी० (एफ) 5-7/94. —राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ग्राम पंचायत डोगीधार, गांव टांगी, जिला कुल्लुम स्वास्थ्य उा केन्द्र खोलने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

I

ज० पी तेंगा,

अभ्युक्त एवं अधिकारी।

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 नवम्बर, 1994

संख्या आवास-6 (एफ०) 6-1/91. —यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि आवास बोर्ड हिमाचल प्रदेश जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 (सी० सी०) के अर्थात्संगत, राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एत निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः ग्राम शांगटी (संजौली) तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न बिन्दुओं में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इस स सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समारुहों (एन० डी० एम०) (ग्रामीण) शिमला, हिमाचल प्रदेश को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश प्राप्त करें।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समारुहों (एन० डी० एम०) (ग्रामीण) शिमला के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : शिमला

ग्राम	खसरा न०	रकबा	
		बीघा	चिस्वा
1	2	3	4
शांगटी (संजौली)	73	1	1
	72	0	6

1	2	3	4
	71	0	7
	128	1	19
	66	1	14
	96	2	18
	98	2	06
	67	0	04
	100	0	02
	101	0	16
	126	2	10
	220/127	3	10
	221/127	0	14
	222/132	4	03
	223/132	2	10
	226/139	1	03
	227/139	1	0
	94	0	18
	95	3	18
	133	0	05
	134	0	07
	130	3	02
	135	1	09
	68	0	16
	131	0	06
	136	0	46
	102	0	07
	224/139	1	0
	129	3	0
	64	0	13
	74	0	13
	93	1	13
	65	1	0
	91	0	10
	92	0	03
	97	3	15

1. प्रत्येक समूह में 100-1-10 (A) 00 000 000 000 000 15

100-1-10 में 100-1-10 प्रत्येक समूह में 100 (A) 00 000 000 000 000 15

1. प्रत्येक समूह में 100-1-10 प्रत्येक समूह में 100 (A) 00 000 000 000 000 15

1. प्रत्येक समूह में 100-1-10 प्रत्येक समूह में 100 (A) 00 000 000 000 000 15

आदेश द्वारा,

गवर्नर 100-1-10 प्रत्येक समूह में 100 (A) 00 000 000 000 000 15

अम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अक्टूबर, 1994

संख्या: 1 (ए0) 3-8/91-अम.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, दुकान तथा वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969 (1970 का 10) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ददाह, जिला सिरमौर में स्थित दुकानों तथा वाणिज्य संस्थानों को इस वर्ष दिनांक 9-11-94 से 20-11-1994 तक राज्य स्तरीय मेला श्री रणुकाजी के समायोजन के उद्देश्य में तथा सप्ताहिक प्रवृत्ति वाले दिन उक्त अधिनियम की धारा 9 तथा 10 (1) के तहत छूट देने की सहायता प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

एस0 एस0 सिद्ध, स
वित्तायुक्त एवं सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 1994

No. Rev. 2 F (6)-7/80-II —In exercise of the powers conferred under section 16 of the Himachal Pradesh Holdings (Consolidation and Fragmentation) Act, 1971, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to cancel the declaration made by the Director, Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh in respect of Tikka Laharu of Village Jawali H. B. No. 76/29, Area 340 acres. Tehsil Nurpur, (now tehsil Jawali), District Kangra, Himachal Pradesh vide Notification No. Rev. (CH) Notification 14 (1) (50.p)/79-5541, dated, 19-11-79 with immediate effect.

By order,

P. T. WANGDI.

Secretary.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

आदेश द्वारा

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या: पी0 सी0 एच0 एच0 एच0 (5) 82/94-1569.—क्योंकि ग्राम पंचायत टीहरा, बिलास खण्ड बगाना, जिला ऊना का अंशक्षण विभागीय अंशकरण (पंचायत) जिला ऊना द्वारा अधि 1-4-92 से 6-1-94 तक किया जिसमें प्रधान के विरुद्ध मना निधि के दुरुपयोग एवं गबन का प्रतीकरण हुआ है और उप-प्रधान पंचायत द्वारा की गई शिकायत पर जिला बिलास एवं पंचायत अधिकारी ऊना द्वारा प्रारम्भिक छानबीन करवाने पर भी श्री चत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत टीहरा, मना निधि के दुरुपयोग एवं छलहरण के निम्न आरोपों में गलित पाए गये हैं:

- (1) यह कि ग्राम पंचायत टीहरा की रोडवर्कही पृष्ठ 42 के अनुसार दिनांक 31-3-1993 की 661 बिलोग्राम का दर 661 बिलोग्राम गड़्डे जिसका का मूल्य 6127.47 रूप्य बनना है, दर्ज है, परन्तु प्रधान द्वारा अनाज का खिलरण नहीं किया गया। इस प्रकार प्रधान ने 606127.47 रूप्य की घनराशि का गबन किया है;

(२) यह कि पंचायत के वाऊचर संख्या ७, दिनांक ५-१-९४ के अन्तर्गत $12' \times 18'$ दूरी मु० २३७६/- रुपये में निम्नलिखित खादी आश्रम सन्तोषगढ़, मेन बाजार ऊना से कय की गई है और वाऊचर प्रधान द्वारा स्वीकृत है, परन्तु वास्तव में मौका पर $12' \times 12'$ पाई गई और इस प्रकार उक्त प्रधान ने सभा निधि से मु० १०५६/- रुपये दुरुपयोग किया है;

(३) यह कि वाऊचर संख्या ५, दिनांक २८-८-९३ के अनुसार वावली मकौहण के निर्माण हेतु १० बोरी सीमेंट मु० १२००/- रुपये में कय किया गया था, परन्तु प्रधान उक्त कय किये गए सीमेंट में ८ बोरी सीमेंट का प्रयोग यथासमय नहीं कर सके जिस कारण सीमेंट खराब हो गया है और इस प्रकार सभा निधि को मु० ९६०/- रुपये की क्षति पहुंची है जिसका उत्तरदायित्व प्रधान का है। अतः मु० ९६०/- रुपये की राशि उनमें वसूली योग्य है;

(४) यह कि निर्माण पुली सनहाल हेतु कय किये गए सीमेंट/सरिया में से स्टॉक रजिस्टर अनुसार दिनांक ५-१-१९९४ को १८ बोरी सीमेंट का मु० १६९०/- रु० में विक्रय किया गया, परन्तु राशि को रोकड़वही में दर्ज न करवाकर उक्त प्रधान द्वारा इस राशि का सीधे खर्च किया गया है।

(५) यह कि उक्त प्रधान श्री चेत राम के नाम मुरम्मत सरायें टीहरा हेतु मु० १५००/- रुपये की पेशगी दिनांक १-१२-९२ से चली आ रही है जिसकी वापसी जांच के समय तक नहीं की गई है। उक्त राशि $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत व्याज की दर से मु० २३५/- रुपये महित वसूली योग्य है, जिसका उक्त प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया है;

(६) यह कि मुरम्मत सरायें तलेहड़ा पर मु० ४८४०/- रुपये व्यय किये गए हैं, जबकि कनिष्ठ अभियन्ता, विकास खण्ड बंगाणा की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार व्यय राशि मु० ३५९४/- रुपये बनती है। इस प्रकार प्रधान ने मु० १२४६/- रुपये का दुरुपयोग किया है और यह राशि उनमें वसूली योग्य है;

(७) यह कि निर्माण पुली सनहाल पर मु० ७५८५१/- रुपये का व्यय किया गया है जबकि कनिष्ठ अभियन्ता विकास खण्ड बंगाणा की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार व्यय राशि मु० ७१४११/- रुपये बनती है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रधान श्री चेत राम द्वारा मु० ४४४०/- रुपये का दुरुपयोग किया गया है, जो कि वसूली योग्य है।

और क्योंकि श्री चेत राम प्रधान, ग्राम पंचायत टीहरा को उपरोक्त कृत्य के लिए उपायुक्त ऊना द्वारा उन्हें दिनांक १-१०-१९९४ को प्रधान पद से निलम्बित किया गया है।

और क्योंकि उपरोक्त वर्णित आरोपों/वैतथ्यों की वास्तविकता को जानने व मामले में पूरी स्थिति सामने लाने के लिए सरकार द्वारा नियमित जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम १९९४ की धारा १४६(१) के अधीन प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए श्री चेत राम प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत टीहरा, विकास खण्ड बंगाणा के विरुद्ध उप सम्भागीय अधिकारी ऊना को जांच अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देते हैं। साथ ही पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड बंगाणा को प्रस्तुत कर्ता अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है, जो कि पंचायत के रिकार्ड के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी रखेंगे।

शिमला-२, ९ नवम्बर, १९९४

संख्या : पी० सी० एच० एच० ए० (५) ६९/९१.—क्योंकि ग्राम पंचायत भुमतीर, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू ने अपने प्रस्ताव दिनांक ९-६-९४ द्वारा पारित किया है कि श्री काली दास, पंच ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पंचायत कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रहा है।

उपरोक्त बारे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कुल्लू के माध्यम से पुष्टि करवाने पर यह तथ्य सामने आया है कि श्री काली दास, पंच, दिनांक 10-1-94 से पंचायत बैठकों से लगातार अनुपस्थित है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(घ) के अन्तर्गत यदि कोई पदाधिकारी छः मास की अवधि में संचालित बैठकों के आधे से ज्यादा में युक्ति-युक्त हेतु के बिना अनुपस्थित रहता है, किसी भी समय हटाया जा सकता है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के अधीन प्राप्त है, श्री काली दास, पंच, ग्राम पंचायत भूमतीर, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (घ) के अन्तर्गत पंच पद से हटाया जाये, उनका उत्तर 15 दिनों के भीतर उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायगा कि वे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव,

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी0) 15-14/83-I. — हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिए बहुकेन्द्रीय योजना (स्ट्रेटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट योजना क्षेत्रों/विशेष क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के नाम से ज्ञात प्राधिकरण की स्थापना करते हैं।

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय शिमला में होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी0) 15-14/83-I, तारीख 14-11-94 द्वारा विघटन किए गए शिमला विनास प्राधिकरण, कुल्लू घाटी विशेष क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, हमीरपुर, धर्मशाला, मण्डी, परवाणू और बरोडीवाला योजना क्षेत्रों के लिये नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण की सभी आस्तियां और उत्तरदायित्व हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण में तुरन्त प्रभाव से अन्तर्गत होंगे।

अधिसूचना संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी) 15-14/83-1, दिनांक 14-11-1994 का परिशिष्ट

योजना क्षेत्र का नाम :

1. बरोटीवाला
2. चम्बा
3. धर्मशाला
4. डलहौजी
5. हमीरपुर
6. मैहतपुर
7. मण्डी
8. नालागढ़
9. पालमपुर
10. नाहन
11. पांवटा साहिब
12. परवाणू
13. रामपुर बुझहर
14. रोहडू
15. सराहों (सिरमौर)
16. शिमला
17. ठियोग
18. ऊना
19. कसौली

विशेष योजना क्षेत्र का नाम :

1. कुल्लू घाटी विशेष क्षेत्र
2. हाटकोटी विशेष क्षेत्र
3. पण्डोह झील
4. चमेरा जलाशय
5. वींग डैम

शिमला-2, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी) 15-14/83-1.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सिटलमेंट्स) के विकास के लिए बहुकेन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए ।

अतः राज्य सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्या पी० डब्ल्यू० (बी)-15(14)/83, तारीख 14-12-1983 द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 और 42(क) के अधीन, स्थापित/गठित शिमला विकास प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा-78 (i) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राधिकरण को तुरन्त प्रभाव से विवर्तित करते हैं।

शिमला-2, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी०) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिए बहुकन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास और चयनित प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्या लोक निर्माण(ख) 28-26/85, तारीख 25 नवम्बर, 1991 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 66 और 67 के अधीन कुल्लू घाटी विशेष क्षेत्र के लिए स्थापित और गठित विशेष क्षेत्र विनाम प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा-78(i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राधिकरण को तुरन्त प्रभाव से विवर्तित करते हैं।

शिमला-2, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी०) (15)-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण का निम्नलिखित रूप से तुरन्त प्रभाव से गठन करने का आदेश देते हैं :—

- | | |
|---|-------------|
| 1. मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश | ... अध्यक्ष |
| 2. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार | ... सदस्य |
| 3. सचिव, (टी० सी० पी०) हिमाचल प्रदेश सरकार | ... सदस्य |
| 4. सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार | ... सदस्य |
| 5. मुख्य प्रशासक, हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण | ... सदस्य |
| 6. मेयर, नगर निगम, शिमला | ... सदस्य |

शिमला-2, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी०) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सेटलमेंट्स) के विकास के लिये बहुकन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत

करके शहरी विकास और उपनिवेशीय व्यवस्थापनों (पैटलमेंट्स) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट योजना क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 (1) के अधीन स्थापित/ पदातिहित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण के रूप में बना रहना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 78 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्राधिकरणों (इन अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित) को तुरन्त प्रभाव से विघटित करते हैं।

अधिसूचना संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 (बी) 15-14/83-1, दिनांक 14 नवम्बर, 1994 का परिशिष्ट

योजना क्षेत्र का नाम	अधिसूचना संख्या व तिथि जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण के रूप में नामांकिदण्ट (डिजीनेट) किया गया था
1. मण्डी योजना क्षेत्र	संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 (बी0एण्ड आर0) (बी0) 4 (10) 4/84, दिनांक 29-7-1985.
2. हमीरपुर योजना क्षेत्र	संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 (बी0एण्ड आर0) 28 (15)/85, दिनांक 13-3-1986.
3. धर्मशाला योजना क्षेत्र	संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 (बी0एण्ड आर0) (बी0) 4 (11)-5/84, दिनांक 21-5-1986.
4. परबाणू योजना क्षेत्र	संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 (बी0एण्ड आर0) (बी0) 15 (1) 8/81, दिनांक 14-8-1986.
5. बरोटीवाला योजना क्षेत्र	संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 (बी0एण्ड आर0) (बी) 15 (1) 3/81, दिनांक 14-8-1986.

आदेश द्वारा,

पी0 एस0 नेगी,
विस्तार्युक्त एवं सचिव।

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4 the 22nd November, 1994

No. 6-13/94-VS.—On the recommendations of Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha and under Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat Regulations,

1992, the Hon'ble Speaker is pleased to frame the following rules for supply of dresses to the Officers of Vidhan Sabha Secretariat who attend the sittings of Vidhan Sabha Sessions.

1. These rules may be called "The Rules for Supply of Dresses to the Officers of the Vidhan Sabha Secretariat. Rules, 1994".

2. These rules shall come into force w.e.f. Budget Session of 1995.

3. *Definitions:—*

- (i) In these rules unless the context otherwise requires, 'Officers' means the Officers of H. P. Vidhan Sabha Secretariat who attends the sitting of Vidhan Sabha Sessions.
- (ii) Vidhan Sabha Session means sitting of Himachal Pradesh Vidhan Sabha.
- (iii) Speaker means, Speaker of H.P. Vidhan Sabha.
- (iv) Secretary means Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
- (v) Amenities Committee means Committee of Vidhan Sabha Members' looking after the welfare of Members and other affairs of H.P. Vidhan Sabha.

4. The uniform will be supplied to the following officers :—

- (i) Secretary ;
- (ii) Editor of Debates ;
- (iii) Table Officer not below the rank of Under Secretary (to be designated).
- (iv) Table Officer in waiting (He will relieve the sitting Table Officer after regular interval.
- (v) Reporters.

5. *Conditions for regulating the issue of Uniform:*

- (i) All the Officers including Reporters of H.P. Vidhan Sabha mentioned in rule 4 will be supplied uniform both winter and summer according to scale indicated in Annexure "A"
- (ii) The Dress (winter and summer) will include the articles and the price admissible for each dress as mentioned in Annexure "A".
- (iii) The price of cloth that would be needed for dresses appended in the annexure "A" is liable to change from time to time keeping in view the market trend.
- (iv) Secretary, H.P. Vidhan Sabha is empowered to accord expenditure sanctioned or purchase of dresses to be supplied to officers within his financial powers.
- (v) To determine the date of actual issue of dresses in the first instance, the date of actual issue of dress will be taken into account and thereafter the due dates would be reckoned from the date it falls due according to time schedule set for in the Annexure "A".
- (vi) It will be obligatory on all the concerned officers to come in dress during the Vidhan Sabha sessions or any other occasion as directed by the Secretary, Vidhan Sabha.
- (vii) The concerned officers shall have to keep the dress neat and clean at their cost and no allowance whatsoever shall be paid for this purpose.
- (viii) In case of loss/damage caused to dress these shall be made good by the defaulters failing which proportionate amount would be recovered from them. However, Hon'ble Speaker may at any time write off the cost of loss or damage of dress where he is satisfied that the loss or damage caused was due to the circumstances beyond the control of officers and not by his negligence or misuse or where no recovery is possible from the defaulters.

- (ix) The supply of uniform is subject to the condition that it cannot be claimed as a right and also the dresses issued do not become the personal property of the officers.
- (x) A Sub-Committee consisting of two officers and two Reporters (one male and other female) will be constituted who would select and purchase the cloth needed for dress after ascertaining the market rates before going for the purchase, samples of the cloth will be got approved from the Secretary, Vidhan Sabha and it should also be borne in mind that the price of cloth being purchased as also the stitching charges prescribed for dress are not exceeded and in case the price of cloth including stitching charges is exceeded the difference between the prescribed ceiling limit and the price so paid shall be borne by the concerned officer.
- (xi) The dress account will be maintained by the Administration Branch on a separate stock register.

ANNEXURE 'A'

Scale of dress, winter/summer admissible to the officers including Reporters of Himachal Pradesh Vidhan Sabha who attend the sittings of Vidhan Sabha Sessions

Sl. No.	Name of Articles	Duration for which sanctioned	Colour of Uniform	Cost of Uniform admissible including stitching charges
1	2	3	4	5

1 WINTER UNIFORM;

Male

- (i) Buttoned up coat and Pant (Terrywool) of Good quality. One uniform in two years. Black for officers and steel grey for Reporters. Rs. 2,000/- per uniform.

Female :

- (i) Shirt } Two shirts, Salwars and Dupattas for two years. One sweater for two years. Rs. 2,000/- per uniform.
 (ii) Salwar }
 (iii) Dupatta }
 (iv) Sweater of good quality. }

2. SUMMER UNIFORM.

Male :

- (i) Safari suit of terry-coat of good quality. One in two years As above Rs. 1,000/- per uniform.

1	2	3	4	5
<i>Female :</i>				
(ii)	Shirt, Salwar, Dupappta (Terrycoat) of good quality.	Two in two years	As above	Rs. 1,000/- per uniform.

LAXMAN SINGH,
Secretary.